

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four

minutes past Fourteen of the Clock.

14.04 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

RAILWAY BUDGET- 2005-06 – GENERAL DISCUSSION

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – (RAILWAYS), 2005-06

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (RAILWAYS)- 2004-05 - contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up item Nos. 10 to 12 together pertaining to Railway Budget, 2005-06.

Shri Jai Prakash (Hissar) was on his legs when the House adjourned yesterday. So, I would request Shri Jai Prakash to continue his speech.

श्री जय प्रकाश (हिंसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि रेल मंत्री जी ने ग्रामीण अंचल के बच्चों के भ्रमण के लिए रेलवे में 75 फीसदी रियायत देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अक्सर देखने में आता है कि जो बच्चे बड़े घरों में पैदा होते हैं, उनके माता-पिता उन्हें पूरे देश का भ्रमण करवा सकते हैं, लेकिन गांव के मजदूर, किसान और छोटे व्यक्तियों के बच्चे, जो अब तक पूरे देश की ज्याग्राफी देखने से वंचित रह जाते थे, उनके लिए यूपीए सरकार और रेल मंत्री जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि डैड बॉडी ले जाने के लिए 50 फीसदी छूट का जो प्रावधान किया गया है, अगर वह छूट शत-प्रतिशत कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

रेल मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। उसमें ग्रुप डी की भर्ती सीधी हो और उनमें ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए जो ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं, जिनका बड़े लोगों से संबंध न हो और जो सही मायने में बेरोजगार हों। अगर ग्रुप डी की भर्ती में ऐसे लोगों को भर्ती किया जाएगा तो रेल मंत्रालय और आगे बढ़ेगा।

हमारे साथी कल कह रहे थे कि रेल के भाड़े में वृद्धि नहीं की गई, लेकिन माल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि रेल भाड़ा पिछली बार भी नहीं बढ़ाया गया था और इस बार भी नहीं बढ़ाया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। माल भाड़े में भी केरोसीन, गैस, जिसे आम लोग प्रयोग में लाते हैं, उनमें जो रियायतें दी गई हैं, वह भी सराहनीय कदम है।

रेल मंत्री जी ने पूरे देश में रेल चलाई है। रेलवे के विस्तार के लिए, रेल डिब्बे बनाने की फैक्ट्री हो, स्लीप्स बनाने की फैक्ट्री हो या कलैक्शन का मामला हो, उसके लिए भी सराहनीय कदम उठाया गया है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लिए जो दिल्ली के साथ तीन तरफ से लगा हुआ है, नई रेलगाड़ी चलाने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। जींद, हरियाणा प्रदेश की राजनैतिक राजधानी है। वहां ओवर ब्रिज की बड़ी भारी समस्या रहती है। वहां एक पुल बनाया जाए जो नेशनल हाईवे नम्बर 71 के ऊपर पड़ता है। ऊंझानाकलां बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। वहां भी एक रेलवे पुल बनाया जाए क्योंकि ऊंझाना शहर दो भागों में बंटा हुआ है और उसके बीच से रेलवे लाइन निकलती है। खासकर जब एफसीआई की स्पेशल ट्रेन लगाई जाती है तो वहां कई-कई घंटे फाटक बंद रहता है। अब हमारे प्रदेश के जो मुख्य मंत्री बने हैं, मैंने आज सुबह ही उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार पैसा देगी। जब सैंटर इसे मंजूरी दे देगा तब हम अपने हिस्से का पैसा जमा करवा देंगे। नरवाना में भी रेलवे का ओवर ब्रिज बनाया जाए। वह भी दो भागों में बंटा हुआ है। जींद से चंडीगढ़ तक एक रेल चलाई जाए। इसके लिए न नया ट्रैक बिछाना है और न कुछ और कार्य करना है। जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ ऑलरेडी ट्रैक है और जींद से कुरुक्षेत्र तक अभी ट्रेन चलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसे चंडीगढ़ तक चलाया जाए। चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। चंडीगढ़ जाने के लिए बसों के किराए से रेल का किराया सस्ता है और रेल की स्वारी ज्यादा सुरक्षित भी है। अगर उस ट्रेन को चंडीगढ़ तक चला दिया जाए तो निम्न वर्ग के लोगों को चंडीगढ़ जाने में आसानी होगी। आज पूरे देश में यह माना जा रहा है कि रेल की स्वारी काफी सुरक्षित है और सस्ती पड़ती है। इसलिए वहां रेल चलाई जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ट्रेन दिल्ली तक क्यों न चलाई जाये ?

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : जींद से दिल्ली तक सीधा ट्रैक है। चौधरी बंसी लाल जब देश के रेल मंत्री थे तब उन्होंने भिवानी से रोहतक -चंडीगढ़ तक ट्रेन चलवाई थी। यही एक इलाका बचा है। अब मैं आपके प्रदेश में आऊंगा। जींद से अमृतसर तक एक ट्रेन चलाई जाये क्योंकि व्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन लोग जींद से व्यास आते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह कि जींद से अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलाई जायेगी तो इससे लोगों को भी फायदा होगा और रेल मंत्रालय की भी आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा बनने के बाद वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झरौदाकलां जींद जिले का ऐतिहासिक स्थान है। वहां जैनी लोग तीर्थ के लिए आते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान में जैनियों का सबसे बड़ा स्थान वहीं है। आप सुनकर हैरान होंगे कि वहां के जाट भी जैन धर्म में विश्वास रखते हैं। देश भर से जैन धर्म के लोग वहां आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके आने-जाने के लिए अगर एक हॉल्ट वहां बना दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में जब रेल लाइन बिछी थी तब किसानों की जमीन दोनों तरफ से उसमें आ गयी थी। वहां कई जगह ऐसी हैं जहां फाटक नहीं है, रेल वे क्रॉसिंग नहीं है। किसानों को अनाज की ढुलाई के लिए, पशुओं के चारे के लिए या खेत में आने-जाने के लिए कोई फाटक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में ऐसे जो 4-5 फाटक हैं, वह आप बनवा दें ताकि किसानों को अनाज ढोने में राहत मिल सके क्योंकि साल में दो बार फसल आती है। उनको कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। फाटक न होने के कारण जब वे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो कभी-कभी ट्रेन आ जाती है। इस जल्दबाजी में गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस जाता है। मेरा कहना है कि इससे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कार्य हैं, वे उन्हें करवायें। मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश में इस तरह के कार्य करवाये जायें। आज रेल ही ऐसा साधन है जो पूरे हिन्दुस्तान को जोड़ने का काम करती है। देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से हम एक भागा की बात करते हैं, राष्ट्रभागा की बात करते हैं, उसी तरह से देश की एकता के लिए रेल भी बहुत बड़ा साधन है। रेल में गरीब आदमी बैठता है, छोटा आदमी बैठता है। बड़े लोग तो हवाईजहाज से यात्रा करते हैं, बसों से यात्रा करते हैं या अपने निजी वाहनों से यात्रा करते हैं। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि रेलों का और अधिक विस्तार किया जाये ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथी कल कह रहे थे कि लालू जी ने जो बजट पेश किया है, उसके कोई मायने नहीं है। उनकी बात भी सही है क्योंकि लालू जी की

जो विचारधारा है, वह उनके मायने से दूर रहती है। हमारे बजट में गरीब आदमी, आम आदमी, किसान की बात कही गयी है। आप देखिये कि जब इनकी सरकार थी, उस समय रेल एक्सीडेंट का क्या प्रतिशत था और यूपीए सरकार बनने के बाद क्या प्रतिशत है? यूपीए सरकार के आने के बाद रेल मंत्रालय का काम अच्छा चल रहा है।

मैंने दूध की बात कही थी। हमारे कई साथी कहते हैं कि दूध रेल में कैसे आयेगा। उनको मालूम नहीं है कि दूध कहां से आता है, दूध की दुलाई कैसे होती है। आज भी मेट्रोपोलिटन सिटीज में 100-100 किलोमीटर दूर से दूध आता है। आप दिल्ली को ही देखिये। दिल्ली में उत्तर प्रदेश से दूध आता है, हरियाणा से आता है। इस बजट में आम आदमी को रियायत मिली है। इस कारण आज हिन्दुस्तान का आम आदमी इस रेल बजट की सराहना करता है लेकिन यह इनको ग्वांरा नहीं खाता। इनके जमाने में सैकिंड क्लास के किराये बढ़ते थे और फर्स्ट क्लास के कम होते थे। आज सैकिंड क्लास का किराया न बढ़ाने का कार्य रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने किया है। यह बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बजट बहुत बढ़िया है। यह आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। अब विपक्ष की भूमिका की बात आती है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाये। बजट पर चर्चा करे, क्विटीसीजम करे लेकिन उसको इस हिसाब से न ले। उसे अच्छे कार्य की सराहना जरूर करनी चाहिए। गलत काम हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। इसलिए मैं सामने बैठे हुए अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रेल मंत्री की खामियां तो आप कर ही देते हैं लेकिन कहीं-कहीं यह भी कहा करो कि रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसकी सराहना करते हैं। मैं एक बार फिर इस रेल बजट का स्वागत करता हूँ। **श्री खारबेल स्वाई (बालासोर)** : हमारे जमाने में कब प्रथम का किराया घटा था और सैकंड क्लास का किराया बढ़ा था? एक उदाहरण दे दें। (व्यवधान) **MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record (Interruptions) ***

श्री जय प्रकाश : आपने तो गोधरा कांड भी करा दिया (व्यवधान) अभी बैनर्जी रिपोर्ट आयेगी* (व्यवधान) मैं माननीय लालू प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि बैनर्जी रिपोर्ट भी वह पेश करें। (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : ये एक ऐसा उदाहरण बता दें। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) *

* Not Recorded

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट काफी प्रगतिशील है। यह बजट जनउपयोगी, गरीबों, आम जनता और बेरोजगारों के लिए है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कई बार रेल बजट इस सदन में आते रहे हैं और सदन उसकी मंजूरी देता रहा है लेकिन सन् 2005-2006 का बजट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यात्रीभाड़ा न बढ़े, मालभाड़ा न बढ़े और दूसरी तरफ उस मंत्रालय को लाम् भी हो, निश्चित रूप से यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बजट है। यात्रियों की सुविधा के लिए जितने प्रस्ताव इसमें आए हैं, जितनी बातें इस रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी के भाषण में उल्लेख की गई हैं, माननीय सदस्यों ने काफी लम्बी बहस और चर्चा उस पर की। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस देश के किसान और इस देश के दूध उत्पादक जिनको यात्रा में पहले कोई राहत नहीं थी, यह पहला बजट है क्योंकि इससे पहले गरीबों को तो राहत मिलती रही है लेकिन छोटे और मझले किसान और दूध उत्पादक के लिए जो रियायत भाड़े में की गई है, यह काफी उल्लेखनीय है।

भारत सरकार की नौकरियों के लिए पहले से ही इन्होंने पहले बजट में व्यवस्था की थी। इस बार इन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए बेरोजगार नवयुवकों के लिए भाड़े में जो सुविधा दी है, जो रियायत दी है, यह बहुत उल्लेखनीय है। एक और विषय जो मुझे रेल बजट पढ़ने से महत्वपूर्ण लगा है, वह यह है कि जो डिब्बों का आरक्षण होता था, उसमें वैकेंसीज का नहीं होता था। इस बार इनकी किताब में, इस रेल बजट के भाषण में हमने पढ़ा कि जो सीट खाली है, उस वैकेंसी को भी यात्रियों की सुविधा के लिए लिखा जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है ताकि इसमें कोई गलत काम अगर इनके कर्मचारी करना चाहें तो वे न कर सकें और यात्रियों को यह जानकारी हो जाए कि वैकेंसी है और सीरियल हमारा है तो हमें निश्चित रूप से जगह मिलेगी।

महोदय, इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े-वर्ग, अल्पसंख्यकों के लिए बिना टेंडर दिए उनको भी रोजगार देने के लिए जो व्यवस्था इस रेल बजट में की है, वह काफी सराहनीय है। ऐसा पहले कभी नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है कि जब से रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ग्रुप-डी की भर्ती शुरू की गयी थी, हर तरफ हाय-तौबा और मास-पीट मची थी। लोगों को काफी परेशानी होती थी। उसमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सराहनीय कदम है। अब अभ्यर्थी जिस रेलवे जोन में रहते हैं, उसी जोन में अपनी परीक्षा में भाग ले सकेंगे और चयनित हो सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

महोदय, कई माननीय सदस्यों के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना है कि हमारे यहाँ यह व्यवस्था नहीं हुई या यह कमी है। इस बार के रेल बजट ने सारे देश भर में महत्वपूर्ण रेल लाइनें और अन्य योजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी रेल बजट एक बार में, सारे देश की रेलवे से जुड़ी समस्याओं और मांगों का निदान नहीं कर सकता और न ही इतने संसाधन किसी सरकार के पास हो सकते हैं। जो संसाधन भारत सरकार और विशेषकर रेल मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं, उसका जितने अच्छे और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने का प्रस्ताव है, वह बहुत खुशी की बात है। माननीय रेल मंत्री जी आज शाम को भी कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने हैं, इस देश के आवाम, गरीब, किसान, बेरोजगार और आम जनता के लिए हर सम्भव अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में मंत्री जी ने कई स्थानों पर जहाँ कभी रेल लाइनें नहीं बिछी थीं, उन स्थानों पर रेल लाइनें बिछाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में कुछ समस्याएं रह गयी हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है उसके लिए दी गयी धनराशि कम है, उसके बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी अवधि निर्धारित करते हुए इसके लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि नेपाल के बॉर्डर पर सीतामढ़ी जिले में बैरगनियां एक स्थान है, जहाँ काफी वॉर् से आन्दोलन चलता रहा है और कई लोगों ने इसके लिए आत्महत्या भी की है। बैरगनियां में एक पुल है जो एक जमाने से वंशी चाचा के नाम से जाना जाता रहा है। यह एक महत्वपूर्ण पुल है जो बैरगनियां और डेंग के बीच स्थित है और यह भारत और नेपाल को जोड़ता है। मैंने यह पुल माननीय मंत्री जी को दिखलाया भी था। वह पुल इस बार के बजट में नहीं आ सका है। मैं आग्रह करूंगा कि वह पुल दो देशों को जोड़ रहा है, उसके लिए वॉर् तक आन्दोलन चला है, उसके लिए आगे प्रावधान किया जाना चाहिए। हाजीपुर और एकहारा के बीच दो जगह ऐसी गुमटी हैं, जहाँ काफी विलम्ब होता है। यह महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो कई जिलों को राजधानी से जोड़ता है। उन दो स्थानों पर ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। रेल बजट की इस किताब में मधुबनी, सीतामढ़ी, बैरगनियां करके कुछ स्थानों का नाम गलती से लिख गया है। इसमें सुधार करना जरूरी है। यह रेल मार्ग चकिया, मधुबन, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाता है।

इसको शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि किताब में यह गलत छप गया है, जबकि मेरे द्वारा आग्रह करने पर ही यह प्रस्ताव में शामिल हुआ था। सीतामढ़ी-नरकटियागंज रेलवे लाइन रेल गाड़ी बमनगामा को पास करती है। इसलिए मेरी मांग है कि बमनगामा में भी हॉल्ट दिया जाए और वहां समुचित स्टेशन का निर्माण कराया जाए। पटना बिहार की राजधानी है। पटना-गया रेलवे लाइन बहुत पुरानी है। वहां काफी भीड़ रहती है, क्योंकि प्रतिदिन लोग आते हैं। वहां न तो कोई नई लाइन बिछी है और न कुछ अन्य कोई ट्रेन शुरू हुई है। इसलिए वहां पर जनता की सुविधा के लिए डीएमयू ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

जहानाबाद और अरबल के बीच एक पुल है। वह पुल काफी पुराना और संकीर्ण है। इस कारण वहां कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए या तो वहां नया पुल बनाया जाए या फिर उस पुल की मरम्मत कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय का, सदन का, माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुजन समाज पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ। मैंने पूरा रेल बजट ठीक से पढ़ा है। रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं दी हैं और उनके लिए जो व्यवस्था की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है।

देश के संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं होगी, तो संविधान बेकार साबित होगा।

सदन में इससे पहले भी रेल बजट पेश किए गए हैं। लेकिन उनमें कहने के लिए भले ही हमारे विपक्ष में बैठे साथी गरीबों, दलितों, वंचितों और पिछड़ों की बात करते रहे हों, उनके साथ खिचड़ी भोज भी करते हों, वास्तव में गले लगाने की बात कभी नहीं करते, हक देने का काम नहीं करते। इस रेल बजट में उन लोगों को, जिन्हें हजारों साल से दबाया गया, पिछड़ा बनाकर रखा गया, एक व्यवस्था देकर सराहनीय काम किया है। रेल बजट में तमाम यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है, रेल लाइनों के दोहरीकरण और कुछ मार्गों का आमान परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनका भी मैं अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ।

रेलवे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के सभी वर्गों को रेल सेवाओं में आरक्षण देने के फैसले का भी मैं स्वागत करता हूँ। बेरोजगार नवयुवकों को नौकरियों के साक्षात्कार में जाने के लिए किराए में 50 फीसदी की रियायत देने की बात कही गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। किसानों और दुग्ध उत्पादकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए रेल मंत्री जी ने जो रियायत दी है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। राजकीय ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत की जो रियायत दी गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ।

मैं इसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। रेल दुर्घटना रोकने हेतु देश भर में चल रहे सामान्य व्यूक्यूम प्रणाली सिस्टम से रेल ट्रेन / रेल गाड़ी को एयर/वात ब्रेक प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी से एक आग्रह है कि नई दिल्ली से कानपुर, पटना, हावड़ा की ओर जाने वाली, सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की स्लीपर बोगी में आरक्षित रेल टिकट के अलावा, प्रतिकारत रेल टिकट पाने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे सभी यात्री रेल ट्रेन में आरक्षित होकर चल सकें। पैसेंजर ट्रेनों की साफ-सफाई व विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा अधिक से अधिक की जानी चाहिए। ताकि यात्री सुविधापूर्वक व सुरक्षित यात्रा कर सकें।

इन दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अर्ध-सैनिक बलों द्वारा सामान्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यात्रियों से झगड़ा होने पर उन्हें मारकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि सभी प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाकर अर्ध-सैनिक बलों के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा, इस बजट में, उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गयी है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ अतिरिक्त प्रावधान होना चाहिए, जिससे ऐसा न लगे कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा या अनदेखी की जा रही है।

इसके साथ-साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी के सामने अपने क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुछ मांग रखना चाहता हूँ। कानपुर से मानिकपुर वाया बांदा रेल मार्ग का दोहरीकरण व विद्युतीकरण किया जाए। बांदा से कानपुर रेल मार्ग के बीच उद्योगनगरी व रेलवे स्टेशन सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए। नई दिल्ली से इलाहाबाद रेल मार्ग में फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली से इलाहाबाद रेल मार्ग के बीच में बिन्दकी रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।

पिछले बजट में भी मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बिल्हौर उत्तर प्रदेश की कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र का जिक्र किया था। उसमें तमाम तरह के क्रॉसिंग हैं, जिसके कारण वहां जाम लगा रहता है। पिछली बार भी मैंने रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रावतपुर मंघना फरुखाबाद लाइन को बंद कर सेंट्रल स्टेशन कानपुर से वाया पनकी मंघना फरुखाबाद तक किया जाए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रावतपुर मंघना, फरुखाबाद जाने वाली ट्रेन का रूट बदलकर कानपुर सेंट्रल से पनकी वाया मंघना फरुखाबाद करने का प्रस्ताव इस बजट में स्वीकार कर लिया जाए या इसके साथ मैंने यह भी निवेदन किया था कि रावतपुर में घंटों जाम लगता है, इसलिए ओवरब्रिज की व्यवस्था वहां की जाए। मेरे क्षेत्र में भावपुर मंघा रेलवे स्टेशन है जहां से नर्सरी के बच्चों व हायर सैकिंडरी स्कूल के बच्चों के गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण वहां दुर्घटनाएं होती हैं। इस बारे में भी मैंने पिछली बार लिखा था। मैं चाहूंगा कि वहां पर ओवरब्रिज या अंडर-पास मार्ग बनाया जाए। इस रेल बजट में गरीबों, वंचितों, दलितों, सभी का ख्याल रखा गया है। कानपुर के अंदर जो तमाम तरह की समस्याएं मैंने बताई हैं विशेष रूप से उनकी ओर ध्यान देने का कार्य करें। इसी के साथ मैं रेल बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*SHRI P. MOHAN (MADURAI): Let me convey my appreciation at the outset congratulating our hon. Railway Ministers both Shri Lalu and Shri Velu for their commendable performance in presenting for the second consecutive year a burden-free Budget. There is no increase in fare for the second year in a row.

Government school students from rural areas and patients travelling by train for treatment and Dalit students are getting rail travel concession. I welcome them.

You have introduced 46 new express trains. Of these 6 will be directly benefitting Tamil Nadu. Hence I thank the

Railway Minister both as an MP from Tamil Nadu and the people's representative from Madurai.

There is another welcome announcement in this Budget with regard to unemployed youth. Last year it was announced that candidates attending interview for Central Government jobs would be getting free travel concession. This year it has been extended to candidates attending job interviews held by State Governments. Let me appreciate this gesture. This has been announced to benefit unemployed youth attending personal interviews for jobs both in Central and State Government services. As such announcements are good but it would be better still if they are implemented. What is there in reality? I have an apprehension whether Railways and authorities are aware of the ground reality which is far from enthusing. As such personal interviews have become a rare thing in selection for posts both in Central and State Governments. There are direct written test selection procedures. In such recruitments personal interviews are rare. Based on performance in competition and skill tests candidates are selected. Hon. Railway Minister has announced free travel concessions only to candidates appearing for personal interviews which are becoming increasingly rare.

* Translation of the speech originally delivered in Tamil.

I know personally two families from Thanjavur. Youth from these families attended written and skill tests more than twice for a single selection at Bangalore for Hubli division. Both the lady candidates from rural areas were called for both written test and skill test for the post of Stenographers last year. They went for medical tests also. This selection was for Railways. But still they were given neither travel concession nor fare reimbursement as part of free travel concession scheme. On enquiry they were informed by the Railway officials that only those who cleared medical tests would be eligible for travel concession when they come with the order of appointment on selection. This happened in August 2004 during the selection of stenographers. This only shows that there is no personal interview in Railways' own selection and hence free travel concession announcement in itself is a vain attempt. So I urge upon the hon. Railway Minister to extend this announced free travel concession to all the unemployed candidates appearing for all recruitment tests both in Central and State Governments.

Both the hon. Railway Ministers Shri Laluji and Shri Veluji recently participated in a function at Madurai. They were accorded a warm reception. Even Laluji picked up some Tamil words like 'Vaango' and 'Pongo' which means 'please come' and 'please go'. He announced of introducing 'Sampark Kranthi Express' a direct express train from Madurai to Chennai. This train has not become popular for two reasons. Departure and arrival timings are unearthly and always tickets are not available even when the trains run without enough passengers. I have taken this to the notice of the officials also. Despite my drawing their attention not much has been done as yet. I am afraid there is an attempt to withdraw or cancel once and for all that train. I charge the Railways that this is a deliberate attempt made both in Delhi and in Madurai.

I have a copy of the ticket to travel by Sampark Kranthi Express train from Delhi to Madurai. The ticket was booked on 6.1.05 for travel on 18.1.05. The ticket was given with waiting list number 2, 3 and 4 and the RAC number 5, 6 and 7.

MR DEPUTY SPEAKER: Shri P. Mohan, if you are reading your printed speech then please lay it on the Table of the House.

SHRI P. MOHAN: Sir, I want to explain one important matter. Then, I will lay it on the Table of the House.

On 18th of January when those passengers went to board the train they noticed that the train was almost empty and there were only very few passengers. More than half of the coach was vacant. Many other coaches were also found vacant. When that is so how can there be non-availability of confirmed tickets for bookings made at least 12 days in advance. It is incomprehensible. This is third time my attention has been drawn to this kind of state of affairs.

Let me come to fund allocation to announced projects and ongoing projects in Tamil Nadu. On the day when Budget was presented this year, our hon. Minister Shri R. Velu met the press. He announced that Rs 438 crore were allocated for projects to be carried out in Tamil Nadu this year. Let me compare it with 'Tamil Nadu at a Glance' statement for the year 2004-05. The allocation made last year was Rs 354.38 crore. In that event Tamil Nadu has got just an increase of Rs 113.62 crore. Last year also new lines were not announced for Tamil Nadu. This year also there are no new projects. Even for ongoing schemes the fund allocation is nil or negligible. For instance 150 kms stretch of Tiruchy-Manamadurai section was conceived at a cost of Rs 187.91 crore. In 2002-03 only Rs 1.05 crore was allocated for this project and it was Rs 0.56 crore in the subsequent year. This year no fund indicated and is also stated that the target date for completion has not been fixed as yet. So is the fate of Trichy-Nagore-Karaikal (200 kms) project. Anticipated cost was Rs 211.36 crore. In 2002-03 the allocation was Rs 93.59 crore and it was Rs 6.85 crore in the subsequent year. Now Thanjavur-Tiruvarur section has been completed and a

mere 30 kms Tiruvarur Nagore-Karaikal link has been left incomplete without fixing target date.

This year's Budget as well as last year's Budget do not carry new gauge conversion projects and new doubling works. Sir, new trains have been announced but no new lines are forthcoming even when there is a huge demand.

Our Minister of State for Railways Shri Velu announced recently about the introduction of weekend express trains directly between Chennai and Madurai soon. But I do not find a mention of it and also Nagar Coil-Coimbatore in the current Budget. I request the hon. Minister to ensure that it does not end up as mere announcement. He had already announced in a press meet at Madurai some months back that there would be a day time passenger train between Madurai and Viluppuram. There is no reference to it in the year's Budget. I urge upon the Railways to run both these trains as announced. But still I welcome the announcement about introduction of new trains considering their utility value to the public.

When it comes to road over bridges Madurai Ellis Nagar, Madurai Vaigai Paalam, Madurai Shanthi Nagar – Koodal Nagar are still under construction. I request the Railway Minister to expedite the completion of these projects while taking up the much emphasised Thirupparankundram ROB project at the earliest. The new line Dindigul-Periyakulam-Sabarimalai has not been announced in this year. Madurai-Anuppukothai-Tuticorin gauge conversion is not there. Gauge conversion of Tuticorin-Tirunelveli is also not there. Doubling of Madurai-Dindigul too has not been taken up this year. Hence I express my deep anguish for their non-inclusion. Madurai-Bodi survey has been done many times in the past. But it has been announced that it is being updated still. This is inappropriate. When TN projects need more than Rs 2500 crore only about 430 crore of rupees have been earmarked that too without new projects. At least Rs 1000 crore must be apportioned at least in the revised Budget this year itself. Kindly look into it.

Now there is a welcome announcement that recruitment for 'D' group will be made soon. At least 85 thousand workers will be recruited and appointed as per the announcements made by Shri Lalu Prasad. It is a welcome decision. But at the same time act apprentices are yet to be appointed.

In 1982 there were many casual labourers. They had gone to Supreme Court and got a direction that they should be appointed. But those who were working in 1980 are left to fend for themselves. They also must be appointed and shown due consideration. What is the mistake they have committed?

I have an order of appointment with me, Southern Railways' appointment order. Office Order No. 130 informs about the appointment of 155 people for the post of Temporary Trackmen. The qualification required is a mere 8th class pass. But you will be surprised and pained to go through the list. Among the people who have been appointed BE graduates are 5, post graduates are 22, graduates are 78, diploma holders are 18, SSLC +ITI are 6, SSLC passed are 38. Most of them or almost all of them are over qualified for this temporary job which calls for a mere 8th class pass. These people with higher qualification should have been considered for suitable higher posts commensurate with their qualification. Now unfortunately they have deprived the best suited 8th class pass candidates who would be doing that job more diligently as per their qualification. I do not mean to say that those who have been appointed now should not have been given that job. But they should have been given better job they deserve. Hon. Railway Minister must look into it. Unemployment problem is taking up its ugly head. The poor and less qualified are left high and dry. Compassionate ground appointments were there in Railways as a last post. That too has been stopped recently. Ban on recruitment must be lifted. I would like to reiterate that the recruitment to the D group posts must go to the ideally suited and qualified candidates as per requirement.

Railway schools were there for the children of railway men in places where there were more railmen living in residential areas nearer to Railway establishments. Many of them are facing closure these days. It was appropriate for Railway Administration to run schools for railmen's children. In Arakkonam just because the railway school was a Tamil medium school it was closed. So also there is a need to improve the quality of service in Railway Hospitals. They must not face closures. Emphasising all my demands again with a hope that they would be considered let me wind up my speech reiterating my support to this Budget.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम वर्ष 2005-06 के रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक रेलों का संबंध है, इसका एक संगठित तंत्र और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। राष्ट्र के विकास में रेलों का योगदान अत्यंत महत्व का है। देश की प्रगति और समृद्धि में रेलों ने अपना विशेष योगदान दिया है। पिछले वर्षों से हमें देखने को मिला कि जिस प्रकार से रेलों का विकास हुआ है, उस तंत्र को संगठित करने की कार्यवाही हुई है लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। पिछली एन.डी.ए. सरकार ने उस असंतुलन को दूर करने के लिये कतिपय उपाय किये थे और उन उपायों में मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि वहां नये ज़ोनों की संरचना की गई और कुछ नई गाड़ियां भी चलाई गईं। किंतु इस बजट को देखने के बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुझे कुछ निराशा ही हुई है। उसे देखने से ऐसा लगा कि शायद रेल मंत्री जी उसमें कुछ करना ही नहीं चाहते थे और भूल गये कि मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, विकसित राज्य है और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। वहां रेल सुविधाये वांछित हैं। उन सुविधाओं के लिये पहल की जाये और वे सुविधाये दी जायें।

उपाध्यक्ष जी, मेरे पास रेल मंत्री जी के वर्ष 2004-05 और 2005-06 के रेल भाण्डा हैं। उनमें उन्होंने पूर्व बजट 2004-05 में जो आव्हान दिए थे, वे केवल घोषणा मात्र रह गए हैं। इनमें चाहे सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस हो या आमाम परिवर्तन की बात हो या रेलों की गति बढ़ाने की बात हो, ये केवल घोषणा मात्र रह गई हैं। यदि माननीय रेल मंत्री जी के भाण्डा को देखा जाये तो उनकी सिर्फ 25 प्रतिशत घोषणायें ही पूरी हुई हैं। जब पिछले बजट की घोषणायें पूरी नहीं हुईं तो जो उन घोषणाओं का हाल हुआ है, वही नई घोषणाओं का भी होगा। आमाम परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था कि सरकार कई किलोमीटर मार्ग का आमाम परिवर्तन करेगी, उसमें चाहे दक्षिण भारत हो, या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। इस दृष्टि से कई रेल लाइनों के आमाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी लेकिन उनमें एक भी लाइन के पूरे होने की संभावना नहीं है। आमाम परिवर्तन के लिये जो धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी, वह नहीं की गई है। मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जो घोषणायें की जाती हैं, उनकी पूर्ति की दिशा में सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है? यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो लम्बे समय तक आमाम परिवर्तन को प्राथमिकता देने के बाद भी वर्ष 2004-05 का कार्य यदि वर्ष 2005-06 में पूरा नहीं होगा और इसमें दो वर्ष और लग जायेंगे फिर उसे प्राथमिकता देने का क्या अर्थ रह जाता है? जो घोषणा की गई, उस पर प्राथमिकता के आधार पर अमल किया जाना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। वहां नीमच-रतलाम रेलमार्ग आमाम परिवर्तन की बात की गई थी। प्रथम चरण में उसकी लागत 105 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जिसे बढ़ाकर 115 करोड़ रुपये किये गये। अब यह राशि 130 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 160 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। जब पहले यह तय किया गया था कि वर्ष 2003-04 में उसे पूरा कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य इस वर्ष 2004-05 में भी पूरा हो पायेगा बल्कि यह 2006-07 में जाकर पूरा हो सकेगा। इस रेल मार्ग का आमाम परिवर्तन संबंधी 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है। जो रह गया है उसे तुरंत पूरा किया जाये। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके साथ ही इन्दौर-रतलाम मार्ग और अजमेर-चित्तौड़ का रेलखंड के आमाम परिवर्तन का कार्य भी होना चाहिये, तभी दूसरे मार्गों से लिंकअप हो सकेगा। इससे दूसरी वैकल्पिक लाइन प्राप्त हो जायेगी। विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। यह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिये भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं चाहूंगा कि इन कार्यों को जो प्राथमिकता दी गई है, उसके मुताबिक शीघ्र पूरा किया जाए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है और इस संदर्भ में मैंने यहां कई बार प्रश्न भी किये हैं और इन मामलों को यहां उठाया भी है कि ओवरब्रिज के संबंध में आपने जो घोषणाएं की हैं कि ओवरब्रिज के मामले में राज्य सरकारें पैसा दें, श्री कांतिलाल भूरिया, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, राज्य सरकार से आग्रह करके एक ओवरब्रिज के लिए राशि स्वीकृत भी करा ली। लेकिन रेलवे के अंदर इतनी उदासीनता है कि वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जहां-जहां इस प्रकार के ब्रिज की घोषणा की गई है, चाहे वह रतलाम हो, जावरा का संदर्भ हो, नीमच का संदर्भ हो या फिर मंदसौर का संदर्भ हो, इस संदर्भ में जो घोषणाएं हुई हैं, जिनके बारे में राज्य सरकार की अनुशंसा है, जहां राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं, उसके बाद रेलवे को जो अपना अंशदान देना चाहिए या रेलवे की तरफ से जो कार्य होना चाहिए, वे कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रेलवे बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, चाहे वह आमाम परिवर्तन की बात हो, चाहे ओवरब्रिज की बात हो या अन्य कार्य हों, इन कार्यों को ठीक से व्यवहार में लाना चाहिए। वे कार्य ठीक से हों, इस बारे में रेलवे को चिंता करनी चाहिए। आखिर इस बारे में जनता कब तक प्रतीक्षा करेगी। मैं चाहता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी बोलें तो इस संबंध में उत्तर देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दो-तीन विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। रेलवे की अपनी कई संस्थाएं और ऐसे संगठन हैं जो रेलवे की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कपूरथला की कोच फैक्ट्री हो, इंटिग्रेटेड कोच फैक्ट्री हो या फिर चित्तूरंजन लोकोमोटिव हो। इस तरह से रेलवे के जो कारखाने और संगठन काम कर रहे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अपनी पूरी क्षमता के बावजूद इसमें कोई 60 प्रतिशत काम कर रहा है, कोई 50 प्रतिशत काम कर रहा है और कोई इससे भी कम काम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें। इनकी कार्य क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाए या कार्य क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि हमें कोचिंग और रेलवे की दूसरी सामग्री बाहर से मंगाने की जरूरत पड़े। हम कपूरथला फैक्ट्री में इतनी क्षमता रखते हैं कि कई चीजें निर्यात कर सकते हैं। जो आज हमें आयात करनी पड़ रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो कोच फैक्टरीज हैं, चाहे इंटिग्रेटेड फैक्ट्री हो, चित्तूरंजन लोकोमोटिव हो, इनका ठीक से उपयोग होना चाहिए, इसके अलावा रेलवे की जो अन्य संस्थाएं हैं, उनका भी ठीक से उपयोग होना चाहिए जैसे भारतीय रेल वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय रेल ट्रेड कारपोरेशन है, भारतीय कंटेनर निगम है और राइट्स है, ये कुछ ऐसे संगठन हैं, जिनका रेलवे को हर दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से और ठीक से उपयोग होना चाहिए। हमें इनका भी लाभ लेना चाहिए। आज भारतीय रेल वित्त निगम का जो लाभ हमें मिलना चाहिए, उसके जरिये से विकास के जो कार्य होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिन संगठनों का मैंने यहां जिक्र किया है, ये संगठन रेलवे के लिये बड़े उपादेय हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हमारे देश के अंदर भी रेलवे के विकास में इनका पूरा-पूरा योगदान हो सके, पूरा-पूरा लाभ हो सके, इनकी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से राइट्स का पूरा उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो रेल वित्त निगम है, उसे कार्यक्षम बनाइये, उसके कार्य को बढ़ाइये। रेलवे का जो कंटेनर निगम है, उसकी क्षमता मांग हो रही है। कंटेनर सर्विसेज बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी सर्विसेज को नहीं बढ़ाया जा रहा है। व्यापारी और उद्यमी कहते हैं कि कंटेनर सर्विसेज बढ़ाइये, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे संगठनों को ठीक से कार्यक्षम बनाया जाए, इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमने यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई बार घोषणाएं की हैं कि हम स्वच्छ प्लेटफार्म देंगे, लेकिन वे घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रह जाती हैं। हम देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से जो कार्य किये जाने चाहिए, वे कार्य नहीं किये जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर जो उपयोगी चीजें हैं, प्रत्येक स्थान पर जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उस आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार रेलवे का विस्तार हो रहा है, यात्रियों के लिए रेलवे के डिब्बों को बढ़ाया जा रहा है, यह ठीक है किन्तु आज देखने में आता है कि किसी गाड़ी में 24 डिब्बे हैं, किसी में 25 डिब्बे हैं, लेकिन जहां तक प्लेटफार्म का संबंध है, प्लेटफार्म इतने छोटे हैं कि 15 से 18 डिब्बों के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है। न तो प्लेटफार्मों को ऊंचा किया गया है और न ही उनका विस्तार किया गया है। इससे महिलाओं, विकलांगों और बच्चों को काफी परेशानी होती है। आज इन प्लेटफार्मों का विस्तार करने की आवश्यकता है और इन्हें ऊंचा किये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अन्यथा इनकी उपयोगिता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग नीचे गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जहां रेलवे के प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है, उस दृष्टि से श्यामगढ़ तथा गरौट रेलवे स्टेशन का विस्तारण किया जाना भी आवश्यक है। उनके शेडज को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, वे काम भी किये जाएं। इसके साथ ही स्टेशन पर शौचालयों की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है। जो प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, कई स्टेशनों पर रात को दो-तीन बजे गाड़ी आती है तो प्लेटफार्म पर अंधेरा रहता है। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बातें की जाती हैं लेकिन सुविधाओं को ठीक से कार्यक्षम नहीं बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से भी माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कतिपय यात्री गाड़ियों का बहुत से स्थानों पर ठहराव आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार सुपरफास्ट गाड़ियां चलती हैं लेकिन वे खाली चलती हैं। किसी स्टेशन में गाड़ी का ठहराव मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि जहां पर आवश्यकता है, वहां पर इन गाड़ियों का ठहराव दिया जाए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन गाड़ियों के ठहराव की बात रखना चाहूंगा। पश्चिम मध्य रेलवे के गरौट रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी निजामुद्दीन एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए जिसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तथा जनता की ओर से भी आग्रह किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे में श्यामगढ़ रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां पर जम्मू तवी सुपरफास्ट का ठहराव दिये जाने के बारे में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार ज्ञापन आदि देकर तथा उनके प्रवास के दौरान नागरिकों द्वारा आग्रह भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे का सुवासरा रेलवे स्टेशन भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर जयपुर इंदौर गाड़ी का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता है जिससे इंदौर से संबंध रखने वाले यात्रियों तथा व्यापारियों को सीधी गाड़ी मिल सके। अगस्त क्रांति जो मुंबई से निजामुद्दीन आती है, उसका ठहराव श्यामगढ़ में किया जाए तो यात्रियों को लाभ होगा।

जैसे कि मैंने अपने पूर्व पत्रों में तथा मेरे राजस्थान के सहयोगी सांसदों ने भी आग्रह किया है कि कोटा और नागदा के मध्य एक मेमू अथवा सामान्य यात्री गाड़ी यात्रियों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए

प्रारंभ की जाए और इस हेतु प्रारंभिक कार्यवाही रेल प्रशासन द्वारा की जा चुकी है तथा परीक्षण के रूप में कुछ भाग पर अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाई गई थीं जो सफल रही थीं। अतः मेरा आग्रह होगा कि कोटा और नागदा के मध्य मेमू गाड़ी चलाई जाए।

अंत में, मैं आरक्षण सुविधा की बात करना चाहूंगा। कुछ स्थानों पर माननीय मंत्री महोदय ने पूर्ववर्ती सरकार के समय कुछ रेलवे के कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्रों की स्थापना की थी। उनमें नीमच, मंदसौर और श्यामगढ़ का जहां नाम था, जहां आरक्षण केन्द्र प्रारंभ हो चुके हैं किन्तु वहां जावरा को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसको सम्मिलित करने के बाद वहां पर कंप्यूटराइज्ड आरक्षण आरंभ नहीं हो सका है वहां स्थपित हो और इन कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्रों की स्थापना के बाद जितने कर्मचारियों की वहां आवश्यकता है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए।

रेलवे संरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ को जहां आपने कई अधिकार दिये हैं, वहां आरपीएफ को संक्षम भी बनाया जाए। यह भी देखा जाए कि वे दुर्व्यवहार न करें, सद्व्यवहार करें, रेलवे संपत्ति की रक्षा करें तथा साथ-साथ यात्रियों को संरक्षण भी प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर माननीय मंत्री महोदय अवश्य योग्य कार्यवाही करेंगे। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे भाग के शांति अंश को सभा के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें।

*अमान परिवर्तन हो, ओल्डर ब्रिजेज हों, उनका कार्य समयावधि में पूरा हो सर्वेक्षण के बाद उज्जैन-रामगंज मंडी, इन्दौर-गोधरा जैसी नयी रेल लाइनों का कार्य हो या नयी रेल गाड़ियों को चालू किया जाना या उनका गंतव्य बढ़ाया जाना जैसी घोषणाएं केवल घोषणा मात्र रह गयी हैं। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को घोषित ऐसी सुविधायें शीघ्र दी जायें। अमान परिवर्तन के कार्य, जिनमें नीमच, रतलाम प्रमुख हैं, इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो व अजमेर चित्तौड़ का अमान परिवर्तन का कार्य रतलाम-महू के अमान परिवर्तन का कार्य भी किया जाये।

जहां तक यात्रियों के खान-पान संबंधी प्रश्न हैं, कुछ ठेकेदारों के द्वारा तो यह कार्य ठीक प्रकार से संपन्न किया जा रहा है लेकिन कुछ ठेकेदारों के द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है और यात्रियों को इससे भारी परेशानी होती है। अतः यदि केंटरिंग व्यवस्था रेलवे प्रशासन ही करे तो बहुत उत्तम होगा। मैं चाहूंगा कि आज मैंने जिन बिंदुओं को यहां पर रखा है उन पर माननीय मंत्री महोदय अवश्य ही योग्य कार्यवाही करेंगे तथा मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि रेल कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से काफी कुछ

* Speech was laid on Table of the House.

किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उनकी मांगों का निराकरण हो सके तथा पश्चिम रेलवे के रतलाम नीमच खंड पर जो अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, वह शीघ्र पूरा कराया जायेगा ताकि यात्रियों को जहां सुविधा हो वहीं रेलवे राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक भी केन्द्रीय मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है। कैसे व्यवस्था चल पाएगी? **â€**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री तो बैठे हैं।

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : हमें बोलने दीजिए। कल भी यह बात उठी थी। मुझे ट्रेन पकड़नी है इसलिए कृपया मुझे अपना भाग करने दीजिए। **â€**(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister of State in the Ministry of Railways is here.

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I must thank you for allowing me to speak on the Railway Budget. It is not an easy task and a lot of hard work has been done by the hon. Minister of Railways in bringing in popular and common man's Railway Budget. He has done an excellent job. A lot of stations have been computerised for booking railway tickets. A number of steps have been announced for passenger amenities and in the information technology sector of Railways. A lot of new trains have been introduced. Concessions for young men and young women travelling for job interviews have been given. A lot of accidents used to take place before, but accident prevention measures have been taken by the present UPA Government, and a lot of accidents have been avoided. We are very happy that these measures have been taken.

Sir, this is one Ministry where sportsmen are helped and appointed in large numbers. There are many other Departments in Government of India that appoint sportsmen, but in respect of strength athletes, Railways is one of the very few Departments that appoints strength athletes, like weightlifters, wrestlers and power-lifters in large scale.

15.00 hrs.

Sir, I request our hon. Minister to increase more sports quota for these strength athletes. That will encourage the sports and our youths who are trained so hard can get employments in the Railways and can earn their livelihood.

This is basically a poor and common man's budget. Everybody have welcomed this popular budget. I do not think there should be any objection to an excellent budget like the budget that has been presented by our hon. Minister. I back this budget wholeheartedly. पिछले बजट में भी हम लोगों ने अपने राज्य से संबंधित समस्याएं रखी थीं, जिन्हें मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी माननीय रेल मंत्री जी से अनेक पत्रों द्वारा कुछ बिंदुओं पर निवेदन किया था। श्रीमन्, उत्तरांचल एक नया प्रदेश बना है, जो देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री-यमुनोत्री, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नानकमत्ता, पुण्यगिरि कलियर शरीफ, ये सभी हमारे यहां के विश्वविख्यात तीर्थस्थल हैं, जिन्हें रेल मार्ग से जोड़ा जाना अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटन एवं इस प्रदेश के विकास के लिए भी आवश्यक है।

मान्यवर, मैं कुछ ऐसी समस्याएं सन् 2005-06 के बजट में फिर से दोहराना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा उत्तरांचल नया राज्य है और हमारे ऑब्जेक्टिव और मेन अर्निंग्स पर्यटन से ही होंगी। इसके लिए नई ट्रेनें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएं। आपने अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। वहाँ के लिए नई ट्रेन के साथ फर्स्ट क्लास AC बोगी भी लगाई जाए। तथा वर्तमान रानीखेत एक्सप्रेस में भी AC-1 की बोगियां काठगोदाम एवं रामनगर हेतु लगाई जाए। लालकुआं, काशीपुर, मुरादाबाद से पंजाब और जम्मूतवी जाने के लिए एक नई गाड़ी चलाई जाए। हमारे यहाँ पंजाबी समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं। जिन्होंने यहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी यह मांग है कि यह गाड़ी जल्दी चलाई जाए तथा यह बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें और इस रेल मार्ग पर नई रेल गाड़ियों के लिए स्वीकृति दें। नानकमत्ता, सितारगंज, खटीमा नये रेल मार्गों के निर्माण के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ पैसा दिया गया है, परन्तु और अधिक पैसे की आवश्यकता है क्योंकि यह रेल लाइन बाद में पूरे उत्तरांचल को जोड़ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 और 72 रायवाला, लच्छीवाला, श्यामपुर एवं मोतीचूर पर रेलवे लाईन पर फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है और राज्य का हाईकोर्ट नैनीताल में है। मेरा निवेदन है कि देहरादून से नैनीताल के लिए रेल सम्पर्क को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए और रोज रेल चलाई जाए।

श्रीमन्, बरेली से टनकपुर वर्तमान में मीटरगेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यही बात कल हमारे सीतापुर के माननीय सांसद ने भी कही थी। बरेली से पीलीभीत होते हुए टनकपुर जो रेल लाइन है, उसे पूर्णागिरी तक बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्णागिरी एक राष्ट्रीय ख्याति का तीर्थस्थान है, जो टनकपुर से करीब 15 किलोमीटर आगे है। इसलिए 15 किलोमीटर रेल लाइन बनाने की और आवश्यकता है। पीलीभीत से बरेली तक के हिस्से को ब्रॉडगेज में बदला जाए।

महोदय, देहरादून-नई दिल्ली, मुख्य शताब्दी गाड़ी में पुराने डिब्बों की जगह नए डिब्बे लगाए जाएं। रामनगर-काशीपुर-जसपुर से धामपुर तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे बहुत पहले हुआ था - उसका क्या हुआ, उसमें कहां तक प्रगति हुई है, इस बारे में मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि वह बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। जैसा मैंने टनकपुर के बारे में कहा कि वह उत्तरांचल को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है, उसी प्रकार रामपुर-काशीपुर-जसपुर रेल लाइन है। इस नई रेल लाइन की हमें बहुत जरूरत है। मेरा निवेदन है कि उसे शीघ्र बनाया जाए। काठगोदाम-दिल्ली के लिए चलाई जाने वाली संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेस में रामनगर एवं काशीपुर से दो बोगियां लालकुआं स्टेशन पर जोड़े जाने की बहुत आवश्यकता है। इससे इस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को भी दिन की एक ट्रेन की सुविधा प्राप्त होने में सहायता होगी।

महोदय, मथुरा-कासगंज-बरेली से लालकुआं तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की बहुत आवश्यकता है। राम नगर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर एवं यहां से देहरादून तक जब नई रेल लाइन बन जाएगी, तो हमारा पूरा उत्तरांचल एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ जाएगा। बाजपुर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने हेतु उसे कंप्यूटराइज किया जाए। ब्रिनाथ एक्सप्रेस को चालू करने के लिए त्रैकिंग से कर्णप्रयाग तक रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार रामनगर के चौरकेरिया जिला अल्मोडा हेतु रेलमार्ग बनाने की आवश्यकता है। इन रेललाइनों का ज्ञात हुआ है कि सर्वे बहुत पहले हो चुका है और यह बहुत जरूरी मार्ग है, इसलिए इस रेलवे लाइन को बनाने की बहुत आवश्यकता है। नेशनल कार्बेट पार्क से रामनगर, वाया कोटाबाग, काठगोदाम जंक्शन तक रेलवे मार्ग की आवश्यकता है।

मान्यवर, आखिर में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महुआखेड़ागंज एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जो मुरादाबाद से जब हम काशी की ओर से उत्तरांचल में एंटर करते हैं, तो उत्तरांचल का सबसे पहला स्टेशन वही पड़ता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि बाहर से जितनी भी गाड़ियां वहां आती हैं, उन सभी का हाल्ट महुआखेड़ागंज पर दिया जाए, यानी वे ट्रेन इस स्टेशन पर जरूर रुकें।

महोदय, अन्त में, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तरांचल की रेल संबंधी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करने की कृपा करें। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए और रेल बजट का समर्थन करते हुए, मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मालभाड़े और स्वारी किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। रेल पूरे देश की आम जनता को लाने ले जाने का काम करती है।

मान्यवर यह बहुत पुराना संगठन है, लेकिन आज जब हम इसकी तुलना दुनिया के विकसित देशों अथवा पड़ोसी देश चीन से तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि हम रेल के मामले में आज भी बहुत पीछे हैं। पूरे चीन में एक शहर को दूसरे से जोड़ने के लिए सब जगह मेट्रो रेल चल रही है जबकि भारत में सबसे पहले केवल कोलकाता में मेट्रो रेल चली और कोलकाता के बाद अब दिल्ली में मेट्रो रेल प्रारम्भ की गई है। अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हम कम से कम विकसित देशों को न मान कर चीन का उदाहरण लें, हमें उसी परिप्रेक्ष्य में काम करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ यह भी देखें कि फ्रांस, जर्मनी और चीन में ढाई सौ किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन हमारे देश में डेढ़ सौ कि.मी. की रफ्तार से भी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं।

महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कम से कम उदाहरण के लिए एक ट्रेन दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक चलाई जाए। अगर ढाई सौ कि.मी. की रफ्तार से न चले तो कम से कम 170-175 कि.मी. की रफ्तार से चले या एक शताब्दी ट्रेन इलाहाबाद तक चलाने की व्यवस्था करें। इलाहाबाद एक सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है तथा शैक्षणिक नगरी भी है।

महोदय, शताब्दी ट्रेनें करीब-करीब सभी महत्वपूर्ण शहरों में चल रही हैं, लेकिन इलाहाबाद इससे उपेक्षित है। हर साल लाखों यात्री पूरे देश और विदेश से इलाहाबाद जाते हैं और वैसे भी इलाहाबाद लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर है। आज आप पूरे देश में देखें कि एक नम्बर प्लेट फॉर्म अच्छा बना हुआ है, लेकिन दो और तीन नम्बर प्लेट फॉर्म आज भी उपेक्षित हैं, उसकी खस्ता हालत है। उन्हें भी सुदृढ़ करके एक नम्बर प्लेट फॉर्म की तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसे भी उसी तरह बनाना चाहिए।

महोदय, स्टेशन पर ज्यादातर नकली पानी बिकता है, जो नीर रेलवे ने बेचना शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम हर कम्पार्टमेंट में पीने के पानी की बोतल की व्यवस्था की जाए ताकि जब रेल यात्री चाहें वे उसे खरीद कर उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, मैं कुछ समस्याएं अपने जिले इलाहाबाद के बारे में भी रखना चाहता हूँ। इलाहाबाद के महत्व के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इलाहाबाद में एक ट्रेन, लखनऊ से इलाहाबाद गंगा-गोमती चलती है। इलाहाबाद की दूरी लखनऊ से 210 कि.मी. की है और उसमें साढ़े चार घंटे का समय लगता है।

मैं चाहूंगा कि एक ट्रेन लखनऊ से इलाहाबाद ढाई घंटे के अंदर चलाई जाए, जो रायबरेली में रुके और वहां रुकने के बाद सीधे इलाहाबाद ढाई घंटे के अंदर पहुंच जाए। (सुवधान) रायबरेली तक जो डबल लाइन होने जा रही है, मैं चाहूंगा कि उसे एक्सटेंड करके इलाहाबाद तक कर दें तो उसमें तेजी से आवागमन हो सकेगा।

महोदय, इलाहाबाद में एक टीएसएल फैक्ट्री है, जो फेब्रीकेशन के भारत के सबसे अच्छे यूनिट्स में से एक मानी जाती है। उसमें रेलवे वैगन बनाने का भी आर्डर मिला है, मैं चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री में वैगन और व्हील बनाने का काम रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि वह सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा संचालित होती है। वह पब्लिक सेक्टर की कम्पनी है और इस समय वह बंदी के कगार पर है। मैं यह भी चाहूंगा कि इलाहाबाद को खास दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहां सेंट्रल जौन हैडक्वार्टर भी है, लेकिन अभी तक उसे डेवलप नहीं किया जा सका है।

जैसा उसे किया जाना चाहिए था। इलाहाबाद में एक आर.ओ.डब्ल्यू बनाने की मांग का हम रेल मंत्री जी को प्रस्ताव देना चाहते हैं। रामबाग में एन.ई.आर. की और नोर्दन सेंट्रल रेलवे की दो रेलवे लाइनें पड़ती हैं और लगभग 3-4 लाख लोग वहां निवास करते हैं, जो रेलवे लाइन से प्रभावित होते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक आर.ओ.डब्ल्यू बनाने का कार्य स्वीकृत किया जाये। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जो धन वांछित होगा, मैं पूरा वायदा करता हूँ कि वह धन दिलवाने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

हमारे पूर्व विधान सभा क्षेत्र में एक जगह सुनाई है। आजादी की लड़ाई में वहां पर लोगों ने रेलवे स्टेशन जला दिया और रेलवे स्टेशन जलाने की वजह से जो रेलवे क्रासिंग फाटक लगा हुआ था, वह बन्द कर दिया गया। रेलवे की यह निश्चित धारणा है कि हावड़ा से लेकर दिल्ली तक कोई नया रेलवे फाटक नहीं बनाया जायेगा। (सुवधान) मैं समाप्त कर रहा हूँ। यह फाटक पहले से था, आजादी की लड़ाई में इसको बन्द कर दिया गया था। मैं चाहता हूँ कि सुनाई का रेलवे फाटक तत्काल चालू किया जाये।

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I should, at the very outset, extend my heartfelt thanks for having given me this opportunity to make my observations and to record my views on the Railway Budget.

Undaunted by jibes and jeers, cat-calls and slogan-shouts and undeterred by walk-outs, Shri Lalu Prasad Yadavji, the Railway Minister stood like a rock and presented the Railway Budget which is welcomed by one and all, and by every cross-section of the society. In spite of the fact that he was pre-occupied in his home State, in his election campaign, he has presented the Budget which is really admirable and appreciable.

I just want to highlight certain salient features of the Budget, and they are, there is no increase in passenger fares; there is no across-the-board increase in freight rates; there is no increase in parcel rates. In spite of all this, the earnings grew by a record 8.3 per cent up to December 2004. About 1400 kms. of broad gauge lines are likely to be added in this fiscal year. Plan outlay is Rs.15,349 crore; Railway Land Development Authority is also planned. The proposals are that 46 new trains are to be introduced in 2005-06; extension of 28 trains are proposed; there would be an increase in the frequency of 10 trains; soon, there would be booking of tickets from landline phones; there will be 75 per cent concession in second class fares to Government and rural school students once a year for study tour; there will be 75 per cent concession in second class fares to girls from rural areas appearing for exams such as medical and engineering; 50 per cent concession in second class fares to farmers and milk producers travelling for training; and full concession in second class to unemployed youth appearing for interviews for Government jobs.

When I highlight and praise the salient features of the Budget, it does not mean that they are without demerits and defects. When I point out the demerits and defects of the Budget, all I would request is that you should set your mind on them and try to set right the things.

The Minister had not paid any attention to increasing allocation for Special Railway Project Fund. He had failed to put in place a monitoring mechanism for ongoing railway projects. There is a lack of any concrete plan for modernisation. Much is talked about modernisation but where is the concrete plan? A concrete project is lacking in this regard.

Revision of classification of food-grains in freight would hit the poor and push up the prices of essential commodities. The Budget did not spell out what the Minister would do to improve passenger amenities. Much is talked about providing amenities to the passengers but concrete proposals and programmes of action are absent.

The PHDCCI President, Shri K.N. Memani, has said that the Railway Budget has failed to carve out a strategy for long term investments through generation of internal surplus for investment purposes. Given the fact that the

Railways are the only high capacity transport mode that can meet the long term growth need of our large economy, measures to capture a substantially larger share of the growing goods traffic and Railways entry into a renewed growth phase are missing.

Now, I would like to talk about certain problems in my constituency. Golden Rock Railway Workshop is one of the oldest workshops as far as Tamil Nadu is concerned. That workshop is shrinking day by day. The number of workers is reduced day by day. Last year also, I had appealed to the Government, particularly to Shri Velu. I will come to that later on. I had appealed to the Government to please see that the Golden Rock Workshop is not only improved but much attention is paid to it. My appeal to you is, there is enough scope to create a coach factory in Golden Rock. There are a number of problems in Golden Rock, which hon. Member, Shri Mohan has also referred.

The condition of railway schools is deplorable. In Golden Rock, particularly, there is one Tamil medium school. I have received a lot of complaints from students, as also parents and labour union leaders. I have also sent a petition to the Minister of State for Railways, my friend, Shri Velu, to look into it. In the Tamil-medium school the existing classes from 1st to Vth standard have been closed and the strength of the students has been drastically reduced from 2000 and odd to a few hundred. If this reduction is allowed at this scale, I am afraid that school will be closed. When Tamil has been accorded the recognition of a classical language – and that is the only Tamil school in the region – will it not be a slap on the faces of Tamils? I have filed a petition signed by a number of people involving a number of irregularities and mal-practices. All this is due to one Headmaster. He may find fault with me if I do not use the word 'Principal'. I am not bothered if he is a Principal or not but all this is due to him. I appeal to you to initiate an inquiry and see what can be done.

In the Golden Rock Railway Colony, there are a number of stall-holders. They are there from time immemorial, even before my birth. There are ancient stall-holders such as tea stall, barber shop, laundry and so on. About hundred people are employed in these stalls.

Unfortunately, there was some tussle between the management and the stall holders as all of a sudden the licence fee was enhanced. They went to the court and ultimately they arrived at some negotiation. Subsequently, they reduced the fee but in between the rent accumulated to a high level. When I was informed of this matter, I met the Chief Works Manager of the Railways at Golden Rock. I met him as also the stall holders and sorted out the matter. Now they are prepared to pay the arrears of rent. But the only thing is that they cannot pay it in a single instalment. That is the problem. Therefore, I would appeal to the hon. Minister, Mr. Velu and also Shri Lalu Prasad Yadav, who is a man of masses, to look into the matter. He is a dynamic leader. Mr. Velu is an efficient and experienced administrator. He was the Joint Registrar of Cooperative Societies in Thanjavur District. In recognition of his services, he was conferred IAS. He served in Tamil Nadu as an IAS officer. He is a popular leader. Therefore, I appeal to them to see that these things are done.

The Tiruchirapalli Corporation wanted to buy some Railway land for expansion of a bus stand as that bus stand was very congested and cramped. As you know, Tiruchirapalli Town is located at the centre of Tamil Nadu. There was some dispute regarding the amount to be paid for that land. The Corporation was willing to pay Rs.6 crore whereas the Railways were demanding Rs.8 crore. The Mayor of the Corporation, Mrs. Sarubala Thondaiman, and myself met the hon. Minister, Mr. Velu. Ultimately, they agreed to give the land at a cost of Rs.6 crore. I would request the hon. Minister to expedite the matter and see that it is completed.

Sir, in Melapudur, a subway is to be constructed for which they are not spending even a single pie. I allocated Rs.20 lakh from MPLAD fund and two MLAs have contributed Rs.10 lakh each for this. Therefore, Rs.40 lakh have been allocated for this subway. So, you please see that it is executed.

I also thank the hon. Minister for having agreed to provide the way leave facility in Mela Ambigapuram. You have already initiated action in this regard. All I request is that it should be completed as early as possible.

I would also request the Railway Minister to favourably consider the plea of Lalgudi and nearby villages for stopping Pallavan Express at Lalgudi Station. The hon. Minister is requested to see that these requests are executed as early as possible.

With these words, I welcome the Budget. I congratulate and commend the dynamic personalities of both the Ministers.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां वर्ष 2005-2006 के रेलवे बजट पर चर्चा चल रही है। पूरे देश में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्गों के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देने के प्रयास किए गए हैं।

लेकिन रेलवे में विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। (ब्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue your speech on Monday.
